महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात एवं मध्यप्रदेश का लोकप्रिय समाचार पत्र

RNI No. MAHHIN/2013/49425
डाक पंजीयन सं. MNW/251/2016-2018
e-paper : www.srushtiagronews.com

Posted at Malad NDPO Dated of Posting
4th to 5th for (1st to 15th issue)
18th to 19th for (16th to 30th issue)

ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

सृष्टि एग्रो

वर्ष -6 | अंक-4 | मुंबई, 16 से 31 मार्च 2018 | मूल्य - 2 रुपए | पृष्ठ - 8

किसानों को समर्पित बजट

किसान, जवान सब पर मेहरबान

मुंबई (कासं)। राज्य में खेती की खराब हो रही हालत और किसानों में बढ़ती नाराजगी के मद्देनजर फडणवीस सरकार का बजट में किसानों को समर्पित दिखाई दे रहा है। राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा और वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में वर्ष 2018-19 का वार्षिक बजट पेश किया। 15 हजार 375 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक राजस्व घाटे का बजट पेश करते हुए कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं व रोजगार के लिए भरपूर प्रावधान किए गए हैं। फलस्वरूप आय और व्यय का गणित गड़बड़ा गया है। किसान को उपज का दोगुना मूल्य दिलाने का वादा करते हुए खेती-किसानी के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। खेती और उससे जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में 75 हजार 909 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स में समानता आने और टैक्स केंद्र का विषय होने के चलते इस बार के बजट में सस्ता-मंहगा कॉलम नदारद है। हालांकि सरकार का दावा है कि जीएसटी के चलते राज्य में 5 लाख 32 हजार नए करदाता जुड़े हैं।

बाजार समितियों में लगेंगी ग्रेडिंग मशीनें: राज्य की कृषि उपज बाजार समितियों में अनाज ग्रेडिंग मशीन लगाई जाएंगी। सरकार की तरफ से बाजार समितियों को मशीन लगाने के लिए 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। बजट में धन राशि आवंटित की गई है।

अपशिष्ट जल प्रबंधन : प्रदेश में 15 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में मुख्यमंत्री ग्रामीण अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना को लागू किया जाएगा। सरकार ने इस नई योजना के लिए साल 2018-19 के लिए 335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

एसटी महामंडल करेगा माल ढुलाई: महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल अब माल ढुलाई के क्षेत्र में उतरेगा। इससे सुदूर गांवों में रहने वाले किसानों के कृषि उत्पाद और माल को किफायती दरों में पहुंचाने में मदद होगी।

महा समाधान और लोकसंवाद केंद्र: प्रदेश के किसानों को मिस्ड कॉल पर खेती से जुड़ी सभी जानकारी मिल सकेगी। किसान खेती के बारे में विशेषज्ञों की सलाह, बीज व खाद, नई योजना और नीति के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश के नागरिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में टोल फ्री नंबर पर जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए लोकसंवाद केंद्र खोला जाएगा।

सुकर्मी पुरस्कार योजना : प्रदेश में काम-काज में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए सुकर्मी पुरस्कार योजना घोषित की गई है।

किसानों के लिए खोला खजाने का मुंह

सिंचाई : जल संसाधन विभाग के लिए 8233 करोड़। अपूर्ण बांध परियोजनाओं में से 50 को पूरा करने का लक्ष्य। कोंकण की बांध परियोजनाओं के लिए 60 करोड़ का प्रावधान। जलयुक्त शिवार के लिए 1500 करोड़। कुओं के निर्माण के लिए 132 करोड़। मांगने पर खेत तालाब योजना के लिए 160 करोड़। सूक्ष्म सिंचाई के लिए 432 करोड़। 93322 कृषि पंप कनेक्शन के लिए 750 करोड़।

कृषि : किसानों की आय दोगुनी करने शाश्वत खेती का विकल्प। कृषि विभाग की तरफ से वन खेती के लिए 15 करोड़। जैविक खेती को बढ़ावा देने 100 करोड़। फलोत्पादन अभियान के तहत फलबाग योजना के लिए 100 करोड़। मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना के लिए 50 करोड़। राज्य की 145 बड़ी बाजार समितियां राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल (ई नाम) पर लाई जाएंगी।

खेती और उससे जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में 75 हजार 909 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया

इन नई योजनाओं की भी बजट में हुई घोषणा

दूध में मिलावट करने वालों को होगा आजीवन कारावास!

मुंबई (कासं)। सरकार दूध में मिलावट की घटनाओं को रोकने के लिए इससे जुड़े कानून को कड़ा करने की तैयारी में है। दूध में मिलावट करने वालों के लिए सजा छह महीने से बढ़ाकर तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक करने से जुड़ा प्रस्ताव विधि व न्याय विभाग के पास भेजा गया है। इस मामले में चार महीनों के भीतर कानूनी सलाह देने को कहा गया है। अन्न व नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने विधानसभा में यह जानकारी दी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए दूध में मिलावट के मुद्दे पर सदन का ध्यान खींचे जाने पर मंत्री बापट ने बताया कि विधि व न्याय विभाग से सलाह मिलने के बाद संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूर कर उसे कानून में बदला जाएगा। राज्य सरकार ने मिलावट के खिलाफ कानून कड़ा करने से जुड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था। इसके जवाब में केंद्र ने कहा कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने ऐसे अपराधों के खिलाफ स्वतंत्र कानून बनाया है। कई राज्यों ने मिलावट करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान किया है। महाराष्ट्र सरकार भी तीन साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान करेगी।

अब 55 दिन में तैयार होगी मूंग की ये नई किस्म

लखनऊ (विसं)। वाराणसी के कुदरत कृषि शोध संस्था ने मूंग की नई किस्म विकसित की है। ये किस्म 55 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। आमतौर पर मूंग की फसल 65-70 दिन में पकती है। इसकी खासियत यह है कि इसके लंबे गुच्छे रहेंगे, फली गहरे हरे रंग की होगी। कुदरत कृषि शोध संस्था के किसान प्रकाश सिंह व रघुवंशी सिंह बताते हैं, 'आमतौर पर मूंग की दूसरी किस्में साठ से सत्तर दिनों में तैयार होती हैं, लेकिन ये किस्म 50-55 दिनों में ही तैयार हो जाती है। ये कई तरह के रोग अवरोधी भी है, जिससे इसमें रोग लगने का भी खतरा नहीं रहता है।' यह किस्म उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब आदि राज्यों के लिए तैयार की है। इस किस्म में प्रति एकड़ छह-सात कुंतल उत्पादन होता है और बीज प्रति एकड़ छह किलो ही लगता है। मूंग कल्याणी किस्म की बुवाई करने से जमीन की उर्वराशक्ति में बढ़ोत्तरी होती है। साथ ही

फसल कटने के बाद हरी खाद भी तैयार हो जाती है। पीला मोजेक, चूर्णित आसिता रोग के प्रति सहनशील रहेगा।

बीजशोधन पांच ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से राइजोबियम कल्चर से बीज का शोधन करके ही बुवाई करनी चाहिए, शोधन के बाद बीज छाया में सुखाकर बुवाई करें।जायद सीजन में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बुवाई करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेमी पर रखें। जबकि खरीफ सीजन 15 से 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर। बुवाई जून-जुलाई में करें। कतार से कतार की दूरी 30 व पौधों की दूरी चार सेमी. रखना चाहिए।

45 किलो की पैकिंग में मिलेगा यूरिया, 242 रुपये होंगे दाम

नई दिल्ली (विसं)। खेतों में उर्वरकों के उपयोग को संतुलित करने के प्रयासों के तहत इस महीने से यूरिया को 50 किलोग्राम के बजाय 45 किलोग्राम की पैकिंग में बेचा जाएगा। उल्लेखनीय है कि यूरिया सबसे आम उर्वरक है और इस पर सरकार बहुत अधिक सब्सिडी देती है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार 45 किलोग्राम यूरिया की एक बोरी की कीमत 242 रुपये होगी। इसमें कर शामिल नहीं है। यह कीमत सरकार द्वारा तय 5,360 रुपये प्रति टन की कीमत पर आधारित है। केंद्र सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य और उत्पादन लागत के बीच के अंतर का वहन करेगी। उर्वरक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कंपनियों को अगले दो महीनों में पुराने 50 किलोग्राम की पैकिंग वाले स्टॉक को बेचने की अनुमति दी गई है। इसका मकसद यूरिया के उपयोग को कम करना और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रसारित करना है। चूंकि यूरिया सस्ता होता है, इसलिए किसान इसका बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं।

गेहूं की तीन नई किस्में विकसित

करनाल (विसं)। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं की एचडब्ल्यू 5207, एचआई 1612 और एचआई 8777 तीन नई किस्मों को विकसित किया है। गेहूं की पहले की किस्मों की अपेक्षा इन किस्मों में प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व 15 प्रतिशत तक अधिक हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने इन किस्मों को कुपोषण को मिटाने और विशेषकर बच्चों और महिलाओं में खून व सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से बनाया है। हरियाणा के करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के गेहूं के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. रवीश चतराथ ने बताया, 'इन नई किस्मों में प्रोटीन के साथ-साथ आयरन, तांबा, जिंक और मैग्नीज भरपूर मात्रा में है। इन किस्मों से न सिर्फ रोटियां स्वादिष्ट बनती हैं, बल्कि ये बिस्कुट और पास्ता बनाने में भी उपयुक्त होंगी।

पहली किस्म: एच डब्ल्यू 5207: गेहूं की एचडब्ल्यू 5207 किस्म को वैज्ञानिकों ने विशेषकर तमिलनाडु राज्य की भूमि के लिए विकसित किया गया है। लीफ रस्ट और स्टीम रस्ट प्रतिरोधी इस किस्म से कम सिंचाई में भी भरपूर पैदावार होती है। इस किस्म में भरपूर पोष्टिक तत्व भी हैं। (शेष पेज दो पर)

सम्पादकीय

शांत हुए किसान

महाराष्ट्र सरकार 180 किलोमीटर लंबा सफर तय कर नाशिक से मुंबई पहुंचने वाले हजारों किसानों के विरोध प्रदर्शन को शांत करने में कामयाब रही है। राज्य सरकार को किसानों की अधिकांश मांगों के आगे झुकना पड़ा है लेकिन इन वादों को पूरा कर पाना आसान नहीं होगा। केवल कुछ मांगें ही लागू करने लायक लग रही हैं और उसके लिए भी सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। अन्य मांगें तो काफी जटिल हैं और उन्हें पूरा करने में कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं। आदिवासी किसानों को सामुदायिक या वन भूमि का मालिकाना हक देना, फसलें खराब होने पर मिलने वाला मुआवजा बढ़ाना और किसानों की सहमति के बगैर ढांचागत परियोजनाओं के लिए कृषि-भूमि का अधिग्रहण नहीं करना जैसी मांगें आसानी से पूरी की जा सकती हैं। लेकिन सभी कृषि ऋणों की बिना शर्त माफी और एम एस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने जैसी दो अहम मांगों को पूरा कर पाना खासा मुश्किल हो सकता है। भले ही महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल घोषित किसान कर्ज माफी योजना का दायरा लिए बढ़ाने पर सहमत हो गई है लेकिन इस कदम से उसके खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ने के अलावा प्रक्रियागत अवरोध भी खड़े हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कर्ज माफी योजना के तहत 340 अरब रुपये का पैकेज घोषित किया था लेकिन अभी तक केवल 138 करोड़ रुपये के कर्ज ही माफ हुए हैं। किसी भी हाल में कर्ज माफी बुनियादी तौर पर एक अविवेकपूर्ण विचार है और उसके कई अनचाहे नतीजे होते हैं। कर्ज अदायगी की संस्कृति पर कुठाराघात करने के अलावा कर्ज माफी योजनाएं पहले से ही बदहाल सहकारी संस्थाओं की वित्तीय सेहत भी खराब करती हैं। इन योजनाओं के चलते बैंक किसानों को कर्ज देने से भी परहेज करने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि किसान साहूकारों के चंगुल में फंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फसलों के लिए अधिक एमएसपी के मुद्दे पर विचार के लिए एक समिति के गठन पर सहमति जताकर राज्य सरकार ने संभवत: अधिक समय लेने की कोशिश की है। इस बारे में अंतिम फैसला निश्चित तौर पर केंद्र की पहल से ही तय होगा। स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी के लिए विस्तृत उत्पादन लागत (सी2) फॉर्मूला अपनाने का सुझाव दिया था जिसमें फसल उत्पादन से जुड़ी सभी तरह की लागत एवं श्रम मूल्य के अलावा खेत का किराया मूल्य भी शामिल किया जाता है। लेकिन सरकार ने इस पर अपना रुख साफ करते हुए कहा था कि वह एमएसपी तय करते समय केवल भुगतान के तौर पर लगी लागत (ए2) के साथ खेती में लगे परिवार के श्रम मूल्य (एफएल) को ही शामिल करेगी।

वैसे सी2 फॉर्मूला लागू कर पाने के लिए जरूरी आंकड़े जुटा पाना खासा मुश्किल है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के तरीके बता रहा नीति आयोग भी ए2 प्लस एफएल फॉर्मूले का सहारा ले रहा है। लेकिन इससे किसानों के खुश होने की संभावना कम है। किसानों के इस प्रदर्शन के नतीजे जो भी रहें, यह सच है कि कृषि क्षेत्र का असंतोष तमाम राज्यों तक फैला है और इस पर बहुत तेजी से ध्यान देने की जरूरत है। खेती से मुनाफा कमाने की क्षमता में आई गिरावट इसकी मूल वजह है। महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र बेहद खराब दौर से गुजर रहा है। पिछले चार में से तीन साल इसकी कृषि विकास दर नकारात्मक रही है। ऐसे में जरूरत यह है कि घाटा उठाने वाली फसलों की खेती को पशुपालन और मत्स्यपालन जैसे सहयोगी कृषि कार्यों के साथ जोड़ दिया जाए। इससे भी अहम होगा कि किसानों की आय के पूरक के तौर पर गैर-कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार एवं आय के अतिरिक्त अवसर पैदा किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो अन्य राज्यों में भी महाराष्ट्र की तरह किसानों के प्रदर्शन होने तय हैं।

पेज 1 का शेष...

गेहूं की तीन नई किस्में...

इसमें 11 प्रतिशत से अधिक प्रोटीन, उच्च लौह तत्व (53.1 पीपीएम), मैग्नीज (47.5 पीपीएम) और जिंक (46.3 पीपीएम) पाया जाता है। इस किस्म से औसतन 40.76 और अधिकतम 59.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार हो सकती है।

दूसरी किस्म : एच आई 8777: गेहूं की एचआई 8777 किस्म बारिश आधारित और प्रायद्वीप क्षेत्रों के लिए विकसित की गई किस्म है। यह किस्म भी लीफ रस्ट और स्टीम रस्ट प्रतिरोधी है। इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा 14.3 प्रतिशत है, जबकि जिंक 43.6 पीपीएम और लौह तत्व 48.7 पीपीएम पाया जाता है। ऐसे में इस किस्म में सामान्य गेहूं की किस्मों से इतर भरपूर पोषक तत्व मौजूद हैं। इस किस्म से किसान औसतन 18.5 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन ले सकते हैं, जबकि अधिकतम 28.8 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन होता है।

तीसरी किस्म: एचआई 1612

गेहूं की यह किस्म बिहार के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विकसित की गई है। अच्छी पैदावार के लिए इस किस्म की समय से बुआई करनी पड़ती है। इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा 11.5 प्रतिशत पाया जाता है, जबकि आयरन और जिंक समेत कई पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा इस किस्म में मौजूद हैं। इस किस्म की बड़ी विशेषता यह है कि सीमित सिंचाई में भी इस किस्म से औसतन 37.6 और अधिकतम 50.5 कुंतल प्रति हेक्टेयर होता है।

गर्मी की मुख्य फसल खरबूजा

खरबूजा एक महत्वपूर्ण कद्दूवर्गीय फसल है, खरबूजे की खेती मुख्यत: उत्तरप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु,, तेलंगाना, आदि राज्यों में की जाती है। खरबूजे के फलों का उपयोग सलाद के रूप में तथा कच्चे फलों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी के रूप में भी किया जाता है। खरबूजे के फलों को मुख्यत: ताजा खाया जाता है। कुछ ग्रामीण लोग इसके कच्चे फलों से सब्जी भी बनाते हैं। यह अपनी मिठास एवं स्वाद के लिये अत्यन्त लोकप्रिय है। खरबूजे के बीजों की गिरी की उपयोग पकवान तथा विभिन्न प्रकार की मिठाईयों में मेवे के रूप में किया जाता है। इसके बीजों में 40-50 प्रतिशत तेल पाया जाता है। खरबूजे के फलों का सेवन मूत्र विकार संबंधी रोगों में लाभकारी होता है। त्वचा रोग एक्जिमा में इसके फलों का रस लगाना लाभकारी होता है। खरबूजे में पोशक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाये जाते है। इसमें कैल्शियम तथा विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है।

जलवायु : खरबूजे के सफल उत्पादन हेतु गर्म एवं शुश्क जलवायु की आवश्यकता होती है। फल पकने के समय विशेष रूप से तेज धूप, गर्म हवा, (लू) फलों में मिठास के लिए आवश्यक होती है लेकिन खरबूजे की फसल को पाले से अधिक क्षति होती है।

मृदा तथा उसकी तैयारी : खरबूजा को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे उत्पादन हेतु रेतीली दोमट मृदाओं को सर्वोत्तम माना जाता है। इसकी खेती के लिए मृदा पी.एच. 6-7 अच्छा माना जाता है। नदियों के किनारे कछारी भूमि में भी खरबूजे को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। खेत को तैयार करने के लिए एक बार मिट्टी पलटन वाले हल से गहरी जुताई करने के बाद 4 से 5 बार कल्टीवेटर या हैरो चलाकर पाटा लगा देना चाहिए।

बुवाई का समय: पर्वतीय क्षेत्रों में खरबूजे की बुवाई अप्रैल-मई माह में की जाती है, जबकि मैदानी इलाकों में बुवाई मध्य जनवरी से मध्य मार्च तक की जाती है। नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में इसे दिसम्बर माह में भी बोया जा सकता है।

बीजदर: बीज बोने के लिए 1.5 मीटर चैड़ी तथा सुविधाजनक लम्बाई वाली क्यारियाँ बनाई जाती हैं। दो क्यारियों के बीच 60 सेंमी. चोड़ी नाली रखी जाती है। क्यारियों में दोनों किनारों पर 90 सेंमी. की दूरी पर बीज बोये जाते हैं। प्रत्येक थाले में 3 से 4 बीज लगभग 1.5 सेंमी. गहराई पर बोना चाहिए। जब पौधों में चार पत्तियाँ आ जाती हैं तो एक पौधे को छोड़कर बाकी कमजोर पौधों को उखाड़ देते हैं।

खाद एवं उर्वरक : खरबूजे की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 200-250 क्विंटल गोबर की खाद तथा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटाश का उपयोग प्रति हैक्टेयर की दर से करना चाहिए।

सिंचाई एवं जल निकास : खरबूजे के सफल उत्पादन हेतु मृदा में नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नदी तट पर बोयी गयी फसल में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। गर्मियों में 5-7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए।

खरपतवार नियंत्रण : खेत में दो से तीन बार निराई करके खरपतवार निकाल देने चाहिए। निराई करते समय बेलों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए।

रोग एवं नियंत्रण

चूर्णिल आसिता: यह फफूदी जनित रोग होता है। इस रोग में पौधों के तनों पर तथा पुरानी पत्तियों के निचले भाग में गोल सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, बाद में ये धब्बे बढ़कर पत्ती की पूरी सतह पर छा जाते हैं जिससे पत्तियों की सतह पर एक सफेद सा पाउडर दिखाई देता है।

नियंत्रण: रोग के लक्षण दिखाई देने पर घुलनशील गंधक के चूर्ण का 0.5 प्रतिशत का छिड़काव 2 से 3 बार करना चाहिए।

मृदुरोमिल आसिता : यह रोग भी फफूंदी जनित है। यह रोग अधिक वर्षा और नमी वाले क्षेत्रों में होता है। इस रोग में पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं।

नियंत्रण : इस रोग के नियंत्रण हेतु डाइथेन एम.-45 नामक दवा की 2 किग्रा मात्रा को 800-1000 लिटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।

कीट एवं नियंत्रण

रेड पम्पकिन बीटल: ये लाल रंग के उड़ने वाले कीट होते हैं, जो पौधों के उगते ही फसल को खाना शुरू करते हैं।

नियंत्रण: इस कीट के नियंत्रण के लिए सेविन 10 प्रतिशत धूल का 15-20 किलोग्राम बुरकाव प्रति हैक्टेयर की दर से करना चाहिए अथवा सेविन 50 प्रतिशत घुलनशील धूल के 0.2 प्रतिशत घोल का छिड़काव करना चाहिए।

फल मक्खी : यह कीट खरबूजे के लिए अत्याधिक हानिकारक कीट है। मादा मक्खी फलों में अण्डे देती है जिसके कारण फलों में सड़न पैदा होने लगती है।

नियंत्रण : इस कीट के नियंत्रण हेतु मैलाथियान का 0.05 प्रतिशत की दर से छिड़काव करना चाहिए।

फलों की तुड़ाई : साधारणत: फलों के पकने पर इनके रंग में परिवर्तन होने लगता है और उनसे तेज खुशबू भी आने लगती है तथा पके हुए फल डंठल से आसानी से अलग हो जाते हैं। खरबूजों की तुड़ाई के लिए सुबह का समय उपयुक्त होता है।

उपज : खरबूजे की उपज निम्न कारकों जैसे-जलवायु, मृदा, खाद एवं उर्वरक तथा सिंचाई आदि पर निर्भर करती है। सामान्यतया खरबूजे की औसत उपज 150-200 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है।

खरबूजे की खेती करने से आर्थिक लाभ : जुताई, बीज, खाद, उर्वरक, मजदूर एवं सिंचाई को मिलाकर खरबूजे की खेती में कुल अनुमानित लागत लगभग 40-45 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर आती है, तथा इससे 2.5 -3 लाख रूपये तक कुल आय प्राप्त होती है जिसमें लागत को निकालकर कुल शुद्ध आय लगभग 2.1 -2.6 लाख रूपये तक हो सकती है।

ब्रजकिशोर शर्मा, डा. महेश सिंह (सहायक प्राध्यापक) एवं अंकित कुमार गोयल
स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर आई.टी.एम.
विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र)

आम के प्रमुख कीट, रोग एवं उनका नियंत्रण

आम का सीजन है। प्रदेश के कई इलाकों में आम के पेड़ों पर अमिया भी देखने को मिल रही हैं। वर्तमान समय में जलवायु में नमी ज्यादा होने के कारण फसल में रोग लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। राजस्थान में 5610 हैक्टेयर से ज्यादा रकबे पर 79,900 टन आम की खेती होती है। भारत विश्व के सबसे बड़े आम निर्यातक देशों में से है लेकिन पिछले कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात को धक्का लगा। कारण था भारतीय आम में कीटनाशक के अवशेषों की बहुत अधिक मात्रा पाया जाना। कीटनाशक के बहुत अधिक प्रयोग से निपटने का अव्वल तरीका यह है कि सही समय पर ही कीट की पहचान कर कीटनाशक या अन्य विधियों से उससे निपटा जाए। कीट की समस्या गंभीर होने और फिर कीटनाशक के भीषण छिड़काव से बचा जाए।

गुठली का घुन (स्टोन वीविल) : यह कीट घुन वाली इल्ली की तरह होता है जो आम की गुठली में छेद करके घुस जाता है और उसके अन्दर अपना भोजन बनाता रहता है। कुछ दिनों बाद ये गूदे में पहुंच जाता है और उसे हानि पहुंचाता है। इस की वजह से कुछ देशों ने इस कीट से ग्रसित बागों से आम का आयात पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था।

रोकथाम : इस कीड़े को नियंत्रित करना थोड़ा कठिन होता है इसलिए जिस भी पेड़ से फल नीचे गिरें उस पेड़ की सूखी पत्तियों और शाखाओं को नष्ट कर देना चाहिए। इससे कुछ हद तक कीड़े की रोकथाम हो जाती है।

जाला कीट (टेन्ट केटरपिलर) : प्रारम्भिक अवस्था में यह कीट पत्तियों की ऊपरी सतह को तेजी से खाता है। उसके बाद पत्तियों का जाल या टेन्ट बनाकर उसके अन्दर छिप जाता है और पत्तियों को खाना जारी रखता है।

रोकथाम : पहला उपाय तो यह है कि एजाडीरेक्टिन 3000 पीपीएम ताकत का 2 मिली लिटर को पानी में घोलकर छिड़काव करें। दूसरा संभव उपाय यह किया जा सकता है कि जुलाई के महीने में किवनालफॉस 0.05 फीसदी या मोनोक्रोटोफास 0.05 फीसदी का 2-3 बार छिड़काव करें

दीमक : दीमक सफेद, चमकीले एवं मिट्टी के अन्दर रहने वाले कीट हैं। यह जड़ को खाता है उसके बाद सुरंग बनाकर ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। यह तने के ऊपर कीचड़ का जमाव करके अपने आप को सुरक्षित करता है।

रोकथाम : इन उपायों से अपने पेड़ों को बचाएं

-तने के ऊपर से कीचड़ के जमाव को हटाना चाहिए।

-तने के ऊपर 5 फीसदी मेलाथियान का छिड़काव करें।

-दीमक से छुटकारा मिलने के दो महीने बाद पेड़ के तने को मोनोक्रोटोफॉस (1 मिली प्रति लिटर) से मिट्टी पर छिड़काव करें।

-दस ग्राम प्रति लिटर ब्यूवेरिया बेसिआना का घोल बनाकर छिड़काव करें।

फुदका या भुनगा कीट : यह कीट आम की फसल को सबसे अधिक क्षति पहुंचाते हैं। इस कीट के लार्वा एवं वयस्क कीट कोमल पत्तियों एवं पुष्पक्रमों का रस चूसकर हानि पहुचाते हैं। इसकी मादा 100-200 तक अंडे नई पत्तियों एवं मुलायम प्ररोह में देती है और इनका जीवन चक्र 12-22 दिनों में पूरा हो जाता है। इसका प्रकोप जनवरी-फरवरी से शुरू हो जाता है।

रोकथाम: इस कीट से बचने के लिए ब्यूवेरिया बेसिआना फफूंद के 0.5 फीसदी घोल का छिड़काव करें। नीम तेल 3000 पीपीएम प्रति 2 मिली प्रति लिटर पानी में मिलाकर, घोल का छिड़काव करके भी निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा कार्बोरिल 0.2 फीसदी या क्विनोलफॉस 0.063 फीसदी का घोल बनाकर छिड़काव करने से भी राहत मिल जाएगी।

फल मक्खी (फ्रूट फ्लाई)- फलमक्खी आम के फल को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। इस कीट की सूंडियां आम के अन्दर घुसकर गूदे को खाती हैं जिससे फल खराब हो जाता है।

रोकथाम : यौनगंध के प्रपंच का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मिथाइल यूजीनॉल 0.08 फीसदी एवं मेलाथियान 0.08 फीसदी बनाकर डिब्बे में भरकर पेड़ों पर लटका देने से नर मक्खियां आकर्षित होकर मेलाथियान द्वारा नष्ट हो जाती हैं। एक हैक्टेयर बाग में 10 डिब्बे लटकाना सही रहेगा।

गाल मीज : इनके लार्वा बौर के डंठल, पत्तियों, फूलों और छोटे-छोटे फलों के अन्दर रह कर नुकसान पहुंचाते हैं। इनके प्रभाव से फूल एवं फल नहीं लगते। फलों पर प्रभाव होने पर फल गिर जाते हैं। इनके लार्वा सफेद रंग के होते हैं, जो पूर्ण विकसित होने पर भूमि में प्यूपा या कोसा में बदल जाते हैं।

रोकथाम : इनके रोकथाम के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करना चाहिए। रासायनिक दवा 0.05 फीसदी फोस्फोमिडान का छिड़काव बौर घटने की स्थिति में करना चाहिए।

आम पर लगने वाले रोग व उनसे बचाव के उपाय

सफेद चूर्णी रोग (पाउडरी मिल्ड्यू) : बौर आने की अवस्था में यदि मौसम बदलने वाला हो या बरसात हो रही हो तो यह बीमारी प्राय: लग जाती है। इस बीमारी के प्रभाव से रोगग्रस्त भाग सफेद दिखाई पड़ने लगता है। अंतत: मंजरियां और फूल सूखकर गिर जाते हैं। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही आम के पेड़ों पर 5 प्रतिशत वाले गंधक के घोल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त 500 लिटर पानी में 250 ग्राम कैराथेन घोलकर छिड़काव करने से भी बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में बौर आने के समय मौसम असामान्य रहा हो वहां हर हालत में सुरक्षात्मक उपाय के आधार पर 0.2 प्रतिशत वाले गंधक के घोल का छिड़काव करें एवं आवश्यकतानुसार दोहराएं।

कालवूणा (एन्थ्रेक्नोस): यह बीमारी अधिक नमी वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। इसका आक्रमण पौधों के पत्तों, शाखाओं और फूलों जैसे मुलायम भागों पर अधिक होता है। प्रभावित हिस्सों में गहरे भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं। प्रतिशत 0.2 जिनकैब का छिड़काव करें। जिन क्षेत्रों में इस रोग की सम्भावना अधिक हो वहां सुरक्षा के तौर पर पहले ही घोल का छिड़काव करें।

ब्लैक टिप (कोएलिया रोग): यह रोग ईंट के भट्टों के आसपास के क्षेत्रों में उससे निकलने वाली गैस सल्फर डाई ऑक्साइड के कारण होता है। इस बीमारी में सबसे पहले फल का आगे का भाग काला पड़ने लगता है इसके बाद ऊपरी हिस्सा पीला पड़ता है। इसके बाद गहरा भूरा और अंत में काला हो जाता है। यह रोग दशहरी किस्म में अधिक होता है। इस रोग से फसल बचाने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि ईंट के भट्टों की चिमनी आम के पूरे मौसम के दौरान लगभग 50 फुट ऊंची रखी जाए। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही बोरेक्स 10 ग्राम प्रति लिटर पानी की दर से बने घोल का छिड़काव करें। फलों के बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान आम के पेड़ों पर 0.6 प्रतिशत बोरेक्स के दो छिड़काव फूल आने से पहले तथा तीसरा फूल बनने के बाद करें। जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाएं तो 15 दिन के अंतराल पर तीन छिड़काव करने चाहिए।

गुच्छा रोग (माल्फार्मेशन) : इस बीमारी का मुख्य लक्षण यह है कि इसमें पूरा बौर नपुंसक फूलों का एक ठोस गुच्छा बन जाता है। बीमारी का नियंत्रण प्रभावित बौर और शाखाओं को तोड़कर किया जा सकता है। अक्टूबर माह में 200 प्रति दस लक्षांश वाले नेप्थालिन एसिटिक एसिड का छिड़काव करना और कलियां आने की अवस्था में जनवरी के महीने में पेड़ के बौर तोड़ देना भी लाभदायक रहता है क्योंकि इससे न केवल आम की उपज बढ़ जाती है अपितु इस बीमारी के आगे फैलने की संभावना भी कम हो जाती है।

पत्तों का जलना : उत्तर भारत में आम के कुछ बागों में पोटेशियम की कमी से एवं क्लोराइड की अधिकता से पत्तों के जलने की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। इस रोग से ग्रसित वृक्ष के पुराने पत्ते दूर से ही जले हुए जैसे दिखाई देते हैं। इस समस्या से फसल को बचाने हेतु पौधों पर 5 प्रतिशत पोटेशियम सल्फेट के छिड़काव की सिफारिश की जाती है। यह छिड़काव उसी समय करें जब पौधों पर नई पत्तियां आ रही हों। ऐसे बागों में पोटेशियम क्लोराइड उर्वरक प्रयोग न करने की सलाह भी दी जाती है। 0.1 प्रतिशत मेलाथिऑन का छिड़काव भी प्रभावी होता है।

डाई बैक : इस रोग में आम की टहनी ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती है और धीरे-धीरे पूरा पेड़ सूख जाता है। यह फफूंद जनित रोग होता है, जिससे तने की जलवाहिनी में भूरापन आ जाता है और वाहिनी सूख जाती है एवं जल ऊपर नहीं चढ़ पाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग ग्रसित टहनियों के सूखे भाग को 15 सेंटीमीटर नीचे से काट कर जला दें। कटे स्थान पर बोर्डो पेस्ट लगाएं तथा अक्टूबर माह में कॉपर ऑक्सीकलोराइड का 0.3 प्रतिशत घोल का छिड़काव करें।

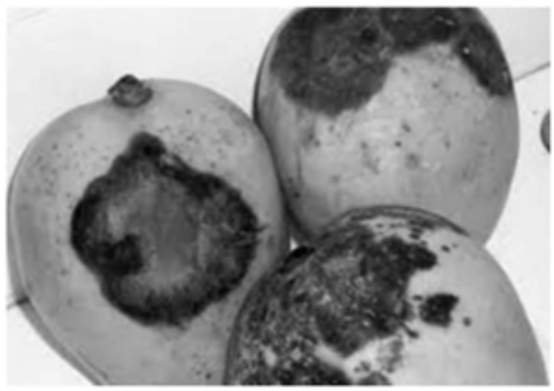

इरफान मोहम्मद पिंजारा, गणेश शिवानंद पुरुषन, राहुल धाकड़ एंड हंसराज धाकड़
कीट विज्ञान विभाग, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, (एम. पि. यू. ए. टी., उदयपुर)

मूंग और उड़द की खेती के लिए आधे दाम पर मिलेगा बीज

औरैया (विसं)। उत्तर प्रदेश में मूंग और उड़द की खेती करने वाले किसानों को पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल सस्ता और आधे रेट पर बीज सरकारी गोदामों पर दिया जा रहा है। 70.40 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मूंग और 69.65 के हिसाब से उड़द का बीज दिया जायेगा। किसान द्वारा खरीदे गये बीज का आधा पैसा खाते में भेजा जायेगा। प्रदेश में मूंग और उड़द की पैदावार में कानपुर मंडल का पहला स्थान है जब कि इलाहाबाद का दूसरे और फैजाबाद का तीसरे पर स्थान है। औरैया जिले के लिए 3466 हेक्टेयर मूंग और 1255 हेक्टेयर उड़द का लक्ष्य है। कृषि विशेषज्ञ राजवीर सिंह ने बताया, उड़द का 30 कुंतल और मूंग का 130 कुंतल बीज सरकारी बीज भंडारों पर पहुंच चुका है। जिसका वितरण भी किसानों में शुरू कर दिया गया है। प्रति हेक्टेयर 15 किलो मूंग या उड़द का बीज बोया जायेगा। जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार ने बताया, लक्ष्य के मुताबिक औरैया जिले के लिए बीज

पर्याप्त मात्रा में आ चुका है बीज का वितरण शुरू करा दिया गया है। आधे रेट पर बीज किसानों को मिलेगा इसके अलावा प्रदर्शन के लिए चिंहित किसानों को पूरा निवेश का पैसा वापस किया जायेगा। किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में कृषि विभाग मूंग और उरद के प्रदर्शन के लिए किसानों को चिंहित कर रहा है। प्रत्येक जिले में अलग-अलग प्रदर्शन का लक्ष्य है। चिहिंत किसानों को एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर में फसल बुआई का प्रावधान है। चिहिंत किसानों द्वारा निवेश किया गया पूरा पैसा डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजा जायेगा। एक हेक्टेयर पर 6700 रूपये का अनुदान मिलेगा।

केवीके को मिला 70 हेक्टेयर का लक्ष्य: कृषि विज्ञान केंद्र परवाह औरैया को मूंग और उरद के लिए 70 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला है। पांच गांवों के 125 किसानों को 50.0 हेक्टेयर भूमि पर मूंग की सम्राट प्रजाति तथा दो गांवो के 50 किसानों को 20.0 हेक्टेयर भूमि में उर्द आईएमयू-243 प्रजाति की बुआई के लिए 10-10 किलो बीज किसानों को दिया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक डा आईपी सिंह ने बीज के साथ किसानों को कीटनाशक किटों का भी वितरण किया।

इन जिलो में होती मूंग तो कहीं उड़द: प्रदेश के जिले संभल में उड़द की पैदावार होती है मूंग नही। इसी प्रकार बरेली में उड़द होती है मूंग नहीं, आगरा, मथुरा में मूंग की पैदावार होती है लेकिन उड़द की नहीं। बलरामपुर और श्रावस्ती में उड़द की पैदावार होती है मूंग की नहीं। हमीरपुर में मूंग है लेकिन उड़द नहीं।

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अभिनेता अक्षय कुमार और महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए 'अस्मिता' का उद्घाटन किया।

कैंसर से बचाएगी गोभी की नई प्रजातियां, हड्डियां भी बनाएगी मजबूत

लखनऊ (विसं)। वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आईआईवीआर) के कृषि वैज्ञानिकों ने गोभी की ऐसी दो प्रजातियां विकसित की हैं। ये दो प्रजातियां वीआरसीएफ-50 और वीआरसीएफ-86 हैं। इन किस्मों में कैंसर रोधी तत्व ग्लूकोसाईनोलेट (सल्फर कंपाउंड) में पाया जाता है। गोभी की इन दोनों नई प्रजातियों में ग्लुकोसाईनोलेट की मात्रा अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो लोगों को कैंसर से बचाने में सहायक होगी। इन प्रजातियों में कैल्शियम की मात्रा भी अन्य प्रजातियों की अपेक्षा अधिक है, जबकि इन प्रजातियों में प्रोटीन की मात्रा कम है, जिससे यूरिक एसिड से परेशान लोगों के लिए ये गोभियां काफी फायदेमंद साबित

हो सकती हैं। इन प्रजातियों के बीज किसानों को जल्द ही मिल सकेंगे।

जल्द नहीं होगी खराब: इन प्रजातियों की गोभी देसी गोभी की अपेक्षा जल्द खराब नहीं होगी। इन प्रजातियों की गोभी सफेद और ठोस होती हैं, ऐसे में इसे दूरदराज के इलाकों में भेजने में भी मुश्किल नहीं होगी। आमतौर पर देसी प्रजातियां स्वाद में अच्छी होती हैं, मगर खेत से तोड़ने में एक-दो दिन में ही फटने लगती हैं।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 20 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली (विसं)। केंद्र सरकार की तरफ से 2016-20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रूपये के साथ चलाई जा रही 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' चौदहवें वित्त आयोग की अवधि समाप्त होने तक चलेगी। इस योजना से 2019-20 तक 20 लाख किसानों के लाभान्वित होने तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 5,30,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यह जानकारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत उनका मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कई केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं चला रहा है।

तापमान बढ़ने के साथ रबी फसलों में लग सकता है रोग

इस महीने तापमान बढ़ने के बाद रबी की फसलों में कई तरह के बदलाव आते हैं। मौसम के हिसाब से किसान कृषि प्रबन्धन के लिए ये उपाय अपना सकते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र, अंबेडकरनगर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. रवि प्रकाश मौर्या बताते हैं, गेहूं में कल्ले निकलने व गांठ बनने की अवस्था संवेदनशील है, इसलिए इन अवस्थाओं में सिंचाई जरूर करें। दोमट भूमि में देरी से बुवाई वाले क्षेत्रों में नाइट्रोजन की एक चौथाई मात्रा सिंचाई के बाद ओट आने पर दें। हल्की मृदा (बलुई दोमट) में नाइट्रोजन की शेष मात्रा का आधा भाग दूसरी सिंचाई के बाद ओट आने पर दें। गेहूं में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देने पर पांच किग्रा जिंक सल्फेट और 16 किग्रा यूरिया को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दी है तो यूरिया के स्थान पर 2.5 किग्रा बुझे हुए चूने के पानी (2.5 किग्रा बुझे चूने को 10 लीटर पानी में शाम को भिगोकर दूसरे दिन पानी निथार कर) का प्रयोग करें। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक रबरी से लेकर मार्च तक उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में दिन और रात दोनों का ही तापमान सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा।

पाक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एग्रो के स्वामित्व व अन्य विषयों से संबंधित विवरण

घोषणा

फार्म-4

1.	प्रकाशन का स्थान	मुम्बई
2.	प्रकाशन अवधि	पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	सुरेश जी. शर्मा
	(क्या भारत का नागरिक है?)	हां
	पता	307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड़ (प), मुंबई-400064
4.	प्रकाशक का नाम	सुरेश जी. शर्मा
	(क्या भारत का नागरिक है?)	हां
	पता	307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड़ (प), मुंबई-400064
5.	सम्पादक का नाम	सुरेश जी. शर्मा
	(क्या भारत का नागरिक है?)	हां
	पता	307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड़ (प), मुंबई-400064
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	सुरेश जी. शर्मा 307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड़ (प), मुंबई-400064

मैं सुरेश जी. शर्मा एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

सुरेश जी. शर्मा

दिनांक: 16.3.2018

प्रकाशक के हस्ताक्षर

दुधारू गाय-भैंसों के लिए जारी होगी 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या

नई दिल्ली (विसं)। भारत सरकार 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या का इस्तेमाल करके दुधारू गायों और भैंसों की पहचान कर रही है। इस संबंध में नौ करोड़ दुधारू मवेशियों की पहचान करने के लिए 148 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कृषि मंत्री राधा सिंह ने लोकसभा में यह जानकारी दी। सिंह ने हिना गावित और पीआर सुंदरम के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इससे पशुओं के वैज्ञानिक प्रजनन, रोगों के फैलने पर नियंत्रण और दूध तथा दुग्ध उत्पादों के व्यापार में वृद्धि करने के उद्देश्य की प्राप्ति होगी। राष्ट्रीय पशु उत्पादकता मिशन के पशु संजीवनी घटक के तहत इसे लागू किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि तकनीक के लिहाज से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पहले ही पशु स्वास्थ्य और उत्पादन संबंधी सूचना नेटवर्क (आईएनएपीएच) विकसित कर चुका है, जिसे 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या वाले पोलीयूरिथिन टैग का प्रयोग करके पशु पहचान संबंधी डाटा अपलोड करने के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। निविदा के आधार पर इस पोलीयूरिथिन टैग की कीमत आठ से 12 रुपये प्रति टैग है। नौ करोड़ दुधारू पशुओं की पहचान करने तथा उन्हें नकुल स्वास्थ्य पत्र (स्वास्थ्य कार्ड) जारी करने के लिए पशु संजीवनी घटक के तहत 148 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

Hindchem Corproation

SUPPER POTASSIUM HUMATE SHINY FLAKES

ZINK EDTA

SEAWEED EXTRACT FLACKES

N.P.K. WATER SOLUBLE FERTILIZER

AMINO ACID

- AMINO+HUMIC SHINY BALLS
- FERROUS SULPHATE19%
- MAGNESIUM SULPHATE 9.6%
- FERROUS EDTA12%
- E.D.T.A. ACID
- CAMPHOR
- SODIUM BICARBONATE
- EDTA DISODIUM
- CITRIC ACID MONOHYDRATE
- MANGANESE SULPHATE 30.5%
- SULPHUR 90% -80WDG
- BORON 20%
- BRONOPOL 25%
- PHOSPHORIC ACID

We Welcome Your Valuable Inquiry
Tel. 022-66998360/61
Fax-022-66450908
Email id: mamta@hindchem.com
Mo. 9004744077

सरकार ने मानी किसानों की मांगें

मुंबई (कासं)। माकपा के किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से नाशिक से मुंबई तक निकाले गए मोर्चे के बाद दबाव में आई प्रदेश सरकार ने आंदोलनकारी किसानों की अधिकांश मांगें मान ली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व किसानों के प्रतिनिधिमंडल के बीच 3 घंटे तक बैठक में सरकार से लिखित आश्वासन लेकर आजाद मैदान पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन समाप्त किए जाने का ऐलान किया।

सरकार ने दावा किया है कि किसानों की 90 प्रतिशत मांगें मंजूर कर ली गई हैं। प्रदेश सरकार ने किसान कर्जमाफी के नियमों को शिथिल कर दिया है। सरकार अब राज्य के किसानों का 30 जून 2017 तक का बकाया कर्ज माफ करेगी। अब तक जून 2016 तक के लिए यह फैसला लागू था। इसके अलावा साल 2001 से किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिलेगा। योजना के तहत अभी साल 2009 के बाद के बकायादार किसानों को लाभ मिला है। कर्जमाफी के लिए आवेदन करने की 31 मार्च की तारीख को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने कर्जमाफी के लाभ के लिए परिवार कि व्याख्या में बदलाव करने का फैसला लिया है। किसान परिवार में पति और पत्नी के नाम पर 1.50 लाख रुपए तक के बकाया कर्ज को माफ किया जाएगा। अब तक परिवार के किसी एक सदस्य को ही 1.50 लाख रुपए तक की कर्जमाफी का लाभ मिल रहा था। कर्जमाफी के लिए आवेदन करने की 31 मार्च की तारीख को बढ़ा दिया गया है।

भूमि को बंजर होने से बचाने के लिए 5199 किसान कर रहे देसी बीजों का संवर्धन

वर्धा (विसं)। रासायनिक खाद तथा बीटी बीजों के बढ़ते इस्तेमाल से धरती की घटती उपजाऊ क्षमता को देखते हुए वर्धा स्थित मगन संग्रहालय एक सराहनीय उपक्रम चला रहा है। मगन संग्रहालय के जरिए चलाए जा रहे विविध उपक्रमों के फलस्वरूप वर्तमान में करीब 260 गांवों के 5 हजार 199 किसान देशी बीजों का संवर्धन और संरक्षण कर रहे हैं। वर्धा शहर में स्थापित मगन संग्रहालय के प्रयासों से आज पूरे जिले में देसी बीजों के प्रति किसानों का आकर्षण बढ़ रहा है। किसान अब देसी बीजों की फसल लेकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। वर्ष 2006 में गिरड में पानलोट कार्यक्रम परिसर के गिरड, पेठ, नान्ही, वेदलाबाद, भवानपुर, मजरा, डोंगरगांव, अंतरगांव, उंदिरगांव, शिवणफल, आर्वी में चलाया गया। इन इलाकों में केवल रासायनिक खेती होती थी। इस दौरान नैसर्गिक खेती के विशेषज्ञ डा. सुभाष पालेकर ने प्राकृतिक खेती की संकल्पना सामने रखी। इसके बाद डा. विभा गुप्ता ने जिले में भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य शुरू किया। इसके जरिए 4 हजार किसानों को तीन दिनों का प्राकृतिक खेती करने का प्रशिक्षण दिया गया। इससे 2 हजार 500 किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाना शुरू किया। अब मगन संग्रहालय प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को मार्गदर्शन करना, समस्या सुलझाना तथा उन्हें जानकारी उपलब्ध करने का कार्य कर रहा है।

बढ़ी आय: इस प्राकृतिक खेती के जरिए वर्ष 2007 में किसानों को उत्पादन में 70 फीसदी खर्च हुआ तथा 30 फीसदी का मुनाफा हुआ। इसमें बीज, खाद व दवा इन तीन घटकों पर कार्य शुरू किए गए। संवर्धन का काम गिरड परिसर के 50 गांवों में बीज संवर्धन यात्रा निकालकर किया गया।

पशु पालकों को मिलेगा मुफ्त में चारे का बीज

औरैया (विसं)। सूखा से ग्रसित क्षेत्रों में प्रदेश के 26 जिलों को शामिल किया गया है। सूखा घोषित जिले के पशु पालक किसानों को पशुओं के चारे के संकट से निपटने के लिए विभाग खाद और बीज निशुल्क दे रहा है। इसके लिए किसानों का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। पशु पालक किसानों को पशुओं के चारे के लिए मुसीबत बनी हुई है। किसानों पर अधिक बोझ न पड़े इसलिए खाद और बीज निशुल्क देने का ऐलान किया है।

किसान फसलों की पैदावार पर तो अपनी जेब से पैसा खर्च कर लेता है लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग का किसान चारे के लिए पैसा कहां से लाकर खर्च करेगा। चारे के संकट से उबरने के लिए किसानों को सिर्फ खेत की जुताई और जुआर (जुंडी, चरी चारा) में पानी लगाने का पैसा वहन करना पड़ेगा। जिले में 1500 पशु पालकों का चयन किया जाना है। दशमलव एक हेक्टेयर से लेकर दशमलव पांच हेक्टेयर तक के किसान का किया जायेगा। चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर शुरू कर दिया गया है।

गन्ने की पैदावार बढ़ने से चीनी उत्पादन में वृद्धि का अनुमान

मुंबई (कासं)। चीनी उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) चालू वर्ष के लिए चीनी उत्पादन के अनुमान को संशोधित करने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में गन्ने की उपज में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण ऐसा किया जा रहा है। 2017-18 के पेराई सीजन की शुरुआत में 2.51 करोड़ टन के अपने आरंभिक अनुमान को संशोधित करते हुए इस्मा ने 18 जनवरी को भारत के चीनी उत्पादन का अनुमान 10 लाख टन तक बढ़ाकर 2.61 करोड़ टन कर दिया। उस समय चीनी उत्पादन का अनुमान महाराष्ट्र में गन्ने की पैदावार के शुरुआती संकेतों के आधार पर लगाया गया था। उस समय परिचालन कर रही अधिकतर मिलों को पेराई के लिए गन्ने की शुरुआती किस्म ही मिली थी। नवंबर-दिसंबर की अवधि में बेमौसमी बारिश इस साल महाराष्ट्र में गन्ने की भरपूर पैदावार में मददगार रही, जबकि पिछले साल सूखे की मार से कम उपज हुई थी। विशेषज्ञों ने गन्ने की सभी किस्मों में सर्वकालिक उच्च पैदावार के साथ राज्य में रिकॉर्ड चीनी उत्पादन का संकेत दिया है। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन पहले ही 2017-18 के चीनी सीजन उत्पादन के अपने पूर्व अनुमान 2.64 करोड़ टन को संशोधित करके 2.9 करोड़ टन कर चुकी है, जबकि महाराष्ट्र का उत्पादन अनुमान 85 लाख टन से बढ़ाकर एक करोड़ टन और कर्नाटक के उत्पादन अनुमान को 25 लाख टन से बढ़ाकर 35 लाख टन किया गया है। आरंभिक अनुमान बताते हैं कि महाराष्ट्र में पेराई के लिए गन्ने की उपलब्धता के आधार पर चीनी उत्पादन 82-85 लाख टन के बीच रहने का अनुमान है।

नागपुर हवाई अड्डे के पास रोड डिवाइडर पर कृत्रिम पौधे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

इस साल सामान्य से कम रह सकती है मानसूनी बारिश

सिंगापुर। इस बार मानसून की बारिश सामान्य से कुछ कम रह सकती है। वजह है अल-नीनो। जून के बाद इसका असर देखने को मिल सकता है। भौगोलिक आंकड़ों पर काम करने वाली निजी अमेरिकी संस्था रेडिएंट सॉल्यूशंस ने यह अनुमान जताया है। रेडिएंट के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी काइल तापले ने कहा कि कम बारिश से भारत में सोयाबीन, मूंगफली और कपास की फसलें प्रभावित हो सकती हैं। पिछले साल भी मानसून की बारिश औसत से कम रही थी। लंबी अवधि के औसत की तुलना में 95 प्रश. बारिश हुई थी, जबकि मौसम विभाग का अनुमान 98 प्रश. का था।

यू एस एग्रोकेम प्रा.लि.
Wholesale Supplier
सूक्ष्म तत्व मिश्रण तरल एवं दानेदार
व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है
प्लाट नं. बी-81, 82, नीलगिरी कॉलोनी, रोड नं. 9 के सामने, वीकेआई एरिया, जयपुर-302013 (राजस्थान)
E-mail : suresh@hindchem.com, Contact : 9004744077

बीटी कपास बीजों के लाइसेंस शुल्क में संशोधन संभव

नई दिल्ली (कासं)। दो साल के अंतराल के बाद केंद्र सरकार 2018-19 के फसल सीजन के लिए जीन संवर्धित (बीटी) कपास बीज की 'ट्रेट वैल्यू' (लाइसेंस शुल्क) में संशोधन कर सकती है। 450 ग्राम वाले पैकेट के लिए इसकी मौजूदा कीमत 800 रुपये है। इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें से 49 रुपये ट्रेट वैल्यू के होते हैं, जिसमें 20-25 रुपये तक की कटौती की जा सकती है। इन दोनों कीमतों को केंद्र निर्धारित करता है। ट्रेट शुल्क वह होता है जिसका भुगतान बीज कंपनियों को लाइसेंस धारकों को कराना पड़ता है। इस मामले में वह देश में वैश्विक दिग्गज मोनसैंटो की संयुक्त उद्यम साझेदार माहिको मोनसैंटो बायोटेक (एमएमबीएल) है। 2017-18 के सीजन के लिए केंद्र ने इसकी ट्रेट वैल्यू को 49 रुपये पर ही बरकरार रखा था, जिसमें सभी कर शामिल थे। केंद्र ने बीटी कपास के दाम भी 800 रुपये प्रति 450 ग्राम पर अपरिवर्तित रखे थे। दिसंबर 2015 के कपास बीज मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत केंद्र द्वारा गठित एक पैनल ने बीटी कपास बीज के दाम पहली बार 2016 में कम किए थे। दामों को 830-1,030 रुपये से घटाकर 800 रुपये कर दिया गया था और प्रति पैकेट 163 रुपये की ट्रेट वैल्यू में करीब 70 प्रतिशत की कमी की गई थी। मई 2016 में जारी किए गए दिशा-निर्देश में ट्रेट वैल्यू को बीज के बिक्री मूल्य के 10 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया था और इसके बाद इसे समय-समय पर कम किया जाता रहा। मोनसैंटो ने कहा कि वह देश में अपने पूरे कारोबार की पुनर्समीक्षा करेगी, यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका है। मोनसैंटो ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की थी। एमएमबीएल ने 2002 के बाद से 50 विभिन्न घरेलू कंपनियों को बीटी कपास बीज प्रौद्योगिकी का उप-लाइसेंस जारी किया था। इसने बीजी-1 प्रौद्योगिकी का सबसे पहला उप-लाइसेंस जारी किया था, जिसका पेटेंट 2006 में खत्म हुआ था। अब यह बीजी-2 का उप-लाइसेंस देती है।

गर्मियों में करे लौकी की उन्नत खेती

कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी का स्थान प्रथम हैं। इसके हरे फलों से सब्जी के अलावा मिठाइया, रायता, कोफते, खीर आदि बनायें जाते हैं। इसकी पत्तिया, तनें व गूदे से अनेक प्रकार की औषधिया बनाई जाती है। पहले लौकी के सूखे खोल को शराब या स्प्रिट भरने के लिए उपयोग किया जाता था इसलिए इसे बोटल गार्ड के नाम से जाना जाता हैं।

जलवायु: लौकी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई गर्मी एवं वर्षा के समय में की जाती है। यह पाले को सहन करने में बिलकुल असमर्थ होती है।

भूमि: इसकी खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती हैं किन्तु उचित जल धारण क्षमता वाली जीवांष्म युक्त हल्की दोमट भूमि इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गयी हैं। कुछ अम्लीय भुमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से करें फिर 2-3 बार हैरों या कल्टीवेयर चलाना चाहिए।

किस्में

कोयम्बटूर-1 यह जून व दिसम्बर में बोने के लिए उपयुक्त किस्म हैं, इसकी उपज 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती हैं जो लवणीय क्षारीय और सीमांत मृदाओं में उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं।

अर्का बहार: यह खरीफ और जायद दोनों मौसम में उगाने के लिए उपयुक्त है। बीज बोने के 120 दिन बाद फल की तुड़ाई की जा सकती है। इसकी उपज 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है।

पूसा समर प्रोलिफिक राउन्ड : यह अगेती किस्म है। इसकी बेलों का बढ़वार अधिक और फैलने वाली होती हैं। फल गोल मुलायम/कच्चा होने पर 15 से 18 सेमी. तक के घेरे वाले होतें हैं, जों हल्के हरें रंग के होतें है। बसंत और ग्रीष्म दोंनों ऋतुओं के लिए उपयुक्त हैं।

पंजाब गोल: इस किस्म के पौधे घनी शाखाओं वाले होते है और यह अधिक फल देने वाली किस्म है। फल गोल, कोमल, और चमकीलें होते हैं। इसे बसंत कालीन मौसम में लगा सकते हैं। इसकी उपज 175 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है।

पूसा समर प्रोलेफिक लाग : यह किस्म गर्मी और वर्षा दोनों ही मौसम में उगाने के लिए उपयुक्त रहती हैं। इसकी बेल की बढ़वार अच्छी होती हैं, इसमें फल अधिक संख्या में लगते हैं। इसकी फल 40 से 45 सेंमी. लम्बें तथा 15 से 22 सेमी. घेरे वाले होते हैं, जो हल्के हरें रंग के होते हैं। उपज 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।

नरेंद्र रश्मि: यह फैजाबाद में विकसित प्रजाती हैं। प्रति पौधा से औसतन 10-12 फल प्राप्त होते हैं। फल बोतलनुमा और सकरी होती हैं, डन्ठल की तरफ गूदा सफेद और करीब 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है।

पूसा संदेश : इसके फलों का औसतन वजन 600 ग्राम होता है एवं दोनों ऋतुओं में बोई जाती हैं। 60-65 दिनों में फल देना शुरू हो जाता हैं और 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है।

पूसा हाईब्रिड-3: फल हरे लंबे एवं सीधे होते है। फल आकर्षक हरे रंग एवं एक किलो वजन के होते है। दोनों ऋतुओं में इसकी फसल ली जा सकती है। यह संकर किस्म 425 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की

उपज देती है। फल 60-65 दिनों में निकलनें लगतें है।

पूसा नवीन : यह संकर किस्म है, फल सुडोल आकर्षक हरे रंग के होते हैं एवं औसतन उपज 400-450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, यह उपयोगी व्यवसायिक किस्म है।

खाद एवं उर्वरक

मृदा की जाँच कराके खाद एवं उर्वरक डालना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त रहता है यदि मृदा की जांच ना हो सके तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर की दर से खाद एवं उर्वरक डालें।

गोबर की खाद : 20-30 टन
नत्रजन : 50 किलोग्राम
स्फूर : 40 किलोग्राम
पोटाश : 40 किलोग्राम

खेत की प्रारंभिक जुताई से पहले गोबर की खाद को समान रूप से टैक्टर या बखर या मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्राए फॉस्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डालना चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा को दो बराबर भागों में बांटकर दो बार में 4-5 पत्तिया निकल आने पर और फुल निकलते समय उपरिवेशन (टॉप ड्रेसिंग) द्वारा पौधो की चारों देनी चाहिए।

बोने का समय

ग्रीष्मकालीन फसल के लिए : जनवरी से मार्च

वर्षाकालीन फसल के लिए : जून से जुलाई

पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर ए पौधे से पौधे की दूरी 1.0 मीटर

बीज की मात्रा

जनवरी से मार्च वाली फसल के लिए : 4-6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर

जून से जुलाई वाली फसल के लिए : 3-4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर

सिंचाई: ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 4-5 दिन के अंतर सिंचाई की आवश्यकता होती है जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता वर्षा न होने पर पडती है। जाड़े मे 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए।

निंदाई गुड़ाई

लौकी की फसल के साथ अनेक खरपतवार उग आते है। अत इनकी रोकथाम के लिए जनवरी से मार्च वाली फसल में 2 से 3 बार और जून से जुलाई वाली फसल में 3-4 बार निंदाई गुड़ाई करें।

मुख्य कीट

लाल कीड़ा (रेड पम्पकिन बीटल)

प्रौढ कीट लाल रंग का होता है। इल्ली हल्के पीले रंग की होती है तथा सिर भूरे रेग का होता है। इस कीट की दूसरी जाति का प्रौढ़ काले रंग का होता है। पौधो पर दो पत्तियां निकलने पर इस कीट का प्रकोप शुरू हो जाता है। यह कीट पत्तियों एवं फुलों को खाता हैए इस कीट की सूंडी भूमि के अंदर पौधो की जडों को काटता है।

रोकथाम

- निंदाई गुडाई कर खेत को साफ रखना चाहिए।
- फसल कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई करना चाहिए जिससे जमीन में छिपे हुए कीट तथा अण्डे ऊपर आकर सूर्य की गर्मी या चिड़ियों द्वारा नष्ट हो जायें।
- सुबह के समय कीट निष्क्रिय रहते है। अत: खेतों में इस समय कीटों को हाथ/जाल से पकड़कर नष्ट कर दें।
- कार्बोफ्यूरान 3 प्रतिशत दानेदार 7 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब के पौधे के आधार के पास 3 से 4 सेमी. मिट्टी के अंदर उपयोग करें तथा दानेदार कीटनाशक डालने के बाद पानी लगायें।
- प्रौढ़ कीटों की संख्या अधिक होने पर डायेक्लोरवास 76 ई.सी. 300 मि.ली. प्रति हेक्टेयर की दर से छिडकाव करें।

फल मक्खी (फ्रूट फ्लाई)

कीट का प्रौढ़ घरेलू मक्खी के बराबर लाल भूरे या पीले भूरे रंग का होता है। इसके सिर पर काले या सफेद धब्बे पाए जाते है। फल मक्खी की इल्लियां मैले सफेद रंग का होता है, जिनका एक शिरा नुकीला होता है तथा पैर नहीं होते हैं। मादा कीट कोमल फलों में छेद करके छिलके के भीतर अण्डे देती है। अण्डे से इल्लियां निकलती है तथा फलों के गूदे को खाती है, जिससे फल सड़ने लगती है। बरसाती फसल पर इस कीट की प्रकोप अधिक होता है।

रोकथाम

- क्षतिग्रस्त तथा नीचे गिरे हुए फलों को नष्ट कर देना चाहिए।
- सब्जियों के जो फल भूमी पर बढ़ रहे हो उन्हें समय समय पर पलटते रहना चाहिए।
- विष प्रलोभिकायों का उपयोग दवाई का साधारण घोल छिडकने से वह शीघ्र सूख जाता है तथा प्रौढ़ मक्खी का प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता है। अत: कीटनाशक के घोल में मीठा, सुगंधित चिपचिपा पदार्थ मिलाना आवश्यक है। इसके लिए 50 मौली, मैलाथियान 50 ई.सी. एवं 500 ग्राम शीरा या गुड को 50 लीटर पानी में घोलकर छिडकाव करे। आवश्कतानुसार एक सप्ताह बाद पुन: छिडकाव करें।
- खेत में प्रपंची फसल के रूप में मक्का या सनई की फसल लगाएं । इन फसलों की ओर यह कीट आकर्षित होकर आराम करता है। ऐसी फसलों पर विष प्रलोभिका का छिड़काव कर आराम करती हुई मक्खियों को प्रभावशाली रूप से नष्ट किया जा सकता है।

मुख्य रोग

चुर्णी फफूंदी

यह रोग फफूंद के कारण होता है। पत्तियों एवं तने पर सफेद दाग और गोलाकार जाल सा दिखाई देता है जो बाद में बढ़ जाता है और कत्थई रंग का हो जाता हैं। पूरी पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती है, पौधों की बढ़वार रुक जाती है।

रोकथाम

- रोगी पौधे को उखाड़ कर जला देंवे।
- घुलनशील गंधक जैसे कैराथेन 2 प्रतिशत या सल्फेक्स की 0.3 प्रतिशत रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखते ही कवकनाशी दवाइयों का उपयोग 10-15 दिन के अंतर पर करना चाहिए।

उकठा (म्लानि)

रोग का आक्रमण पौधे की भी अवस्था में हो सकता है। यदि रोग का आक्रमण नए पौधे पर हुआ तो पौधे के तने का जमीन की सतह से लगा हुआ भाग विगलित हो जाता है और पौधा मर जाता है। इस रोग के प्रभाव से कभी-कभी तो बीज अकुंरण पूर्व ही सड़कर नष्ट हो जाता है।

रोग के प्रमुख लक्षण पुरानी पत्तियों का मुरझाकर नीचे की ओर लटक जाना होता है व ऐसा प्रतीत होता है कि पानी का अभाव है कि जबकि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी रहती है तथा पत्तियों के किनारे झुलस जातें है। ऐसे लक्षण दिन में मौसम के गर्म होने पर अधिक देखे जा सकते हैं। पौधे धीरे-धीरे मर जाता है, ऐसे रोगी मरे पौधों की बेल को लम्बवत काटने पर संवाहक उत्तक भूरे रंग के दिखाई देते हैं।

रोग प्रबंधन : रोग की प्रकृति बीजोढ़ व मृदोढ़ होने के कारण नियंत्रण हेतु बीजोपचार बेनलेट या बाविस्टिन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करते हैं तथा लंबी अवधि का फसल चक्र अपनाना जरूरी होता है।

तुड़ाई : फलों की तुड़ाई उनकी जातियों पर निर्भर करती है। फलों को पूर्ण विकसित होने पर कोमल अवस्था में किसी तेज चाकू से पौधे से अलग करना चाहिए।

उपज

प्रति हेक्टेयर जून-जुलाई और जनवरी-मार्च वाली फसलों में क्रमश 200 से 250 क्विंटल और 100 से 150 क्विंटल उपज मिल जाती है।

लव कुमार, प्रफुल्ल कुमार, डॉ जितेंद्र त्रिवेदी, डॉ धनंजय शर्मा, डॉ. अमित दीक्षित
कृषि महाविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

गर्मियों में केले की खेती में करें उचित सिंचाई प्रबंधन

मार्च-अप्रैल के महीने में जब तापमान बढ़ने से कई फसलों में नमी की कमी हो जाती है, केले की फसल में अच्छी गुणवत्ता के केले की पैदावार लेने के लिए, इस समय खेत में सही सिंचाई प्रबंधन करना चाहिए। अगले दो महीने में तापमान बढ़ जाता है, ऐसे में किसानों सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, आजकल किसान सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन गर्मियों में ड्रिप काम नहीं करता है।

केला गर्म मौसम में होने वाली फसल है, इस की खेती के लिए 30-40 डिग्री वाले क्षेत्र ज्यादा सही माना जाता है। लेकिन गर्मी के मौसम यानी मई-जून के महीनों में तेज गरम हवा से पौधों को बचाने के लिए सही इंतजाम रखना जरूरी होता है। तेज गर्म हवा केले के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है।

अपने क्षेत्र की आबोहवा और खेत की उपजाऊ ताकत के आधार पर उम्दा किस्म के केले की बुवाई करनी चाहिए। टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे की फसल तकरीबन एक साल में तैयार हो जाती है।

समय-समय पर हटाए खरपतवार: इस समय गर्मियों में खेत में इतनी सिंचाई करनी चाहिए, जिससे खेत में नमी बनी रहे। खेत की पानी को सोखने की क्षमता भी ज्यादा होनी चाहिए, जिस से बारिश का पानी ज्यादा समय तक खेत में खड़ा न रह सके। घार में केला तैयार होने में तकरीबन 100-140 दिन का समय लगता है, टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों में 8-9 महीने बाद फूल आना शुरू होता है और तकरीबन एक साल यानी 12 महीने में फसल तैयार हो जाती है। इसलिए समय को बचाने के लिए और जल्दी आमदनी लेने के लिए टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे को ही लगाना चाहिए।

खड़ी फसल में जैसे ही कोई बीमारी वाला पौधा दिखाई दे, तो फौरन उसे उखाड़ कर जला दें और फसल पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह के मुताबिक फौरन कारगर बीमारीनाशक दवा का छिड़काव करें। केला ज्यादा पानी की मांग करने वाली फसल है, पानी की बचत और कम पानी में ज्यादा रकबे की सिंचाई करने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाएं और फसल पर मल्चिंग का इस्तेमाल कर पानी को धूप और हवा द्वारा उड़ने से बचाएं।

करें निराई: केले की फसल को ज्यादा खाद की जरूरत होती है, इसलिए खाद की खुराक मिट्टी की जांच के बाद ही तय करें। अक्टूबर के महीने में पौधे के चारों तरफ गन्ने की सूखी पत्तियां या पुआल वगैरह की 10-15 सेंटीमीटर परत बिछा दें। पौधों पर फूल यानी फल लगना शुरू हो जाए, तो पौधों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें सहारा देने की जरूरत होती है। सहारा देने के लिए बांस के डंडों से सहारा देना चाहिए। घार में लग रहे केले की लंबाई और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नर फूल काटना जरूरी होता है। जून महीने में लगाए गए केले के पौधों में अगले साल मई महीने में फूल निकलना शुरू होता है। पौधे पर फूल दिखाई देने के 30 दिन बाद पूरी घार पर केले बनने लगते हैं।

वैज्ञानिक विधि से करें पशुओं के चारे का भंडारण

पशुओं से ज्यादा दूध उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक चारे की आवश्यकता होती है। इन चारों को पशुपालक या तो खुद उगाता है या फिर कहीं और से खरीदता है। चारे की फसल उगने का एक खास समय होता है जो कि अलग-अलग चारे के लिए अलग-अलग है। चारे को ज्यादा हरी अवस्था में पशुओं को खिलाया जाता है। चारे की कमी से बचने के लिए पशुपालक पहले से ही चारे का भंडारण कर लेते है ताकि कमी के समय उसका प्रयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जा सके। लेकिन इस तरह से भंडारण करने से उसमें पोषक तत्व बहुत कम रह जाते है। इसी चारे का भंडारण यदि वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो उसकी पौष्टिकता में कोई कमी नहीं आती है।

घास को सुखाकर रखना (हे बनाना): हे बनाने के लिए घास को इतना सुखाया जाता है जिससे कि उसके नमी कि मात्रा 15-20 प्रतिशत तक ही रह जाए इससे जीवाणुओं की एन्जाइम क्रिया रुक जाती है, लेकिन इससे चारे की पौष्टिकता में कमी नहीं आती। हे बनाने के लिए लोबिया बरसीम, लूसर्न, सोयाबीन, मटर आदि।

इसके अलावा ज्वार, नेपियर, जौ, बाजरा, आदि घासों का प्रयोग किया जा सकता है। लेग्यूम्स घासों में पाचक तत्व अधिक होते हैं तथा इसमें प्रोटीन व विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए ये फसलें बहुत उपयुक्त होती है। हे बनाने के लिए चारा सुखाना के लिए निम्नलिखित तीन विधियों में से कोई भी विधि अपनाई जा सकती है।

चारे को परतों में सुखाना: जब चारे की फसल में फूल आने लगते है तो उसे काटकर परतों में पूरे खेत में फैला देते हैं और खेतों में तब तक पलटते रहते हैं जब तक कि उसमें पानी की मात्रा लगभग 15 प्रतिशत तक न रह जाए। इसको इकट्ठा करके ऐसी जगह रखे जहां बारिश का पानी न आ सके। इस प्रक्रिया से पशुपालक चारे का भंडारण कर सकता है।

चारे को गट्ठरों में सुखाना: इसमें चारे को काटकर 24 घण्टों तक खेत में पड़ा रहने देते हैं। इसके बाद इसे छोटी-छोटी ढेरियों अथवा गट्ठरों में बांध कर पूरे खेत में फैला देते हैं। इन गट्ठरों को बीच-बीच में पलटते रहते हैं, जिससे नमी की मात्रा घट कर लगभग 18 प्रतिशत तक हो जाए।

चारे को तिपाई विधि से सुखाना: जहां भूमि अधिक गीली रहती हो और जहां बारिश अधिक होती हो ऐसे स्थानों पर खेतों में तिपाइयां गाढ़कर चारे की फसलों को उन पर फैला देते हैं।

इस प्रकार वे भूमि के बिना संपर्क में आए हवा व धूप से सूख जाती है। कई स्थानों पर घरों की छत पर भी घासों को सुखा कर हे बनाया जाता है।

सूचना

पाक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एग्रो में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों व लेखों में समाविष्ट सभी बातों की जांच-परख कर पाना संभव नहीं है विज्ञापनों में अपने उत्पादनों अथवा अपनी सेवाओं के बारे में विज्ञापनदाता जो दावे करते हैं, सृष्टि एग्रो समाचार पत्र उसकी कोई गारंटी नहीं लेता।
विज्ञापनों में किए गए दावों की पूर्ति यदि विज्ञापनदाता द्वारा नहीं होती है तो उसके लिए पाक्षिक सृष्टि एग्रो समाचार पत्र समूह के मुद्रक, सम्पादक, प्रकाशक व मालिक किसी भी रूप में जवाबदेह नहीं होंगे, कृपया इसे ध्यान में रखें। अतः हम पाठकों से अनुरोध करते हैं विज्ञापन में उल्लेखित बातों के संदर्भ में कोई भी करार करने से पूर्व उसके बारे में आवश्यक छानबीन कर लें।

2200 करोड़ की कल्याण योजनाओं का खाका तैयार

मुंबई (कासं)। महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माणकार्य कामगार मंडल के पास 6 हजार करोड़ रुपए की राशि जमा है। विधान परिषद में प्रदेश के श्रम मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर ने यह जानकारी दी। बताया- मंडल को उपकर के माध्यम से यह राशि मिली है। यह निधि मजदूरों के कल्याण पर खर्च की जाएगी। मजदूरों के लिए 2200 करोड़ रुपए की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तावित हैं। सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य किरण पावसकर ने नियम -97 के तहत अल्पकालीन चर्चा के माध्यम से मजदूरों की विभिन्न समस्याओं का मुद्दा उठाया था। जवाब में निलंगेकर ने कहा-कामगार मंडल के माध्यम से मजदूरों का पंजीयन करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की अवधि एक माह और बढ़ाई जाएगी। सरकार ने 7 लाख मजदूरों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मजदूरों को घर देने के लिए मंडल के माध्यम से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। राज्य में 5 लाख घरों का निर्माणकार्य शुरू हो गया है। 10 हजार नए घरों का प्रस्ताव आया है। साल भर में 1 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। श्रम मंत्री ने कहा कि राज्य में साल 2014 से अभी तक 34 लाख नए ईपीएफ खाता खोले गए हैं।

इससे पता चलता है कि इतने लोगों को रोजगार मिला है। इस पर पलटवार करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस सदस्य पावसकर ने कहा कि राज्य में 34 लाख रोजगार पैदा होने का दावा गलत है। क्योंकि अधिकांश लोग एक कंपनी से नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। कंपनी छोड़ने के बाद कर्मचारियों का नया ईपीएफ खाता खोला जाता है। प्रदेश में एमआईडीसी क्षेत्र में कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे।

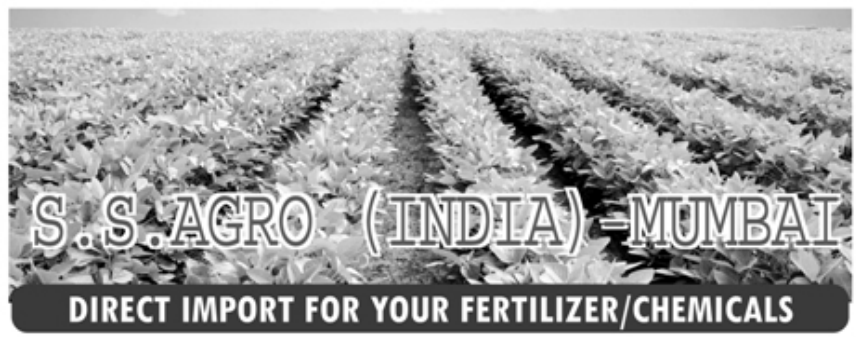

DIRECT IMPORT FOR YOUR FERTILIZER/CHEMICALS

- ☐ ZINK EDTA/COPPER
- ☐ EDTA/FF/EDTA
- ☐ 100% WATER SOLUBLE
- ☐ FERTILIZER (NPK)
- ☐ HUMIC ACID
- ☐ SEAWEED EXTRACT
- ☐ AMINO ACID
- ☐ POTASSIUM HUMATE
- ☐ FULVIC ACID
- ☐ EDDHA
- ☐ NATCA
- ☐ BRASSINOLIDE
- ☐ DAP
- ☐ SODAASH
- ☐ SODIUM SULPHIDE
- ☐ AMONIUM CLORIDE
- ☐ SODIUM BICARBONATE
- ☐ CALCIUM CARBIDE
- ☐ PHOSPHORIC ACID
- ☐ TRI SODIUM PHOSPHATE
- ☐ CITRIC ACID
- ☐ STPP

ALL KIND OF INORGANIC
ORGANIC CHEMICALS
CONTACT NO. 022-6710-3722

सभी फसलों के किसान हैं परेशान

राज्य में अच्छी पैदावार के बावजूद फसलों का कारोबार लागत के मुकाबले बेहद कम कीमत पर होने से राज्य के किसानों में बढ़ रहा रोष

सुरेश शर्मा

मुंबई। महाराष्ट्र में उत्पादित ज्यादातर कृषि जिंसों का कारोबार बहुत कम कीमतों पर हो रहा है और ये कीमतें किसानों के लिए लाभकारी नहीं है। इसी वजह से दूसरे राज्यों की तरह इस राज्य के ज्यादातर किसान ज्यादा जिंसों की बुआई कर रहे हैं जिनके लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने पहले वादा किया था। लेकिन अब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी कोशिशें व्यर्थ हैं और अगले साल वे इस उत्साह से अपनी कोशिश जारी नहीं रख पाएंगे। महाराष्ट्र में मुख्यतौर पर धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, तुअर, मूंग, उड़द, चना और अन्य दालों की फसलें उगाई जाती हैं। यह राज्य तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन प्रमुख तिलहन फसलें हैं। नकदी फसलों में कपास, गन्ना, हल्दी और सब्जियां-प्याज शामिल हैं। राज्य के ज्यादातर किसान आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इन ज्यादातर जिंसों का कारोबार कम कीमतों पर हो रहा है। तिलहन और चने की कीमतों में कुछ सुधार दिख रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने आयात शुल्क बढ़ाते हुए चने के आयात के लिए दरवाजे बंद कर दिए जो एक प्रमुख रबी फसल है। वहीं तेल का आयात भी घटेगा और तिलहन बीज की घरेलू कीमतों में भी सुधार हो रहा है। लेकिन कई लघु और सीमांत किसानों को राहत नहीं मिली है। मिसाल के तौर

पर महाराष्ट्र के चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान है जो भारतीय चीनी मिल संगठन (इस्मा) के मुताबिक 42 लाख टन से बढ़कर इस साल 1.01 करोड़ टन हो सकता है। चीनी की कीमतों के कम होने से राज्य के गन्ना किसानों की स्थिति ज्यादा गंभीर ही होगी। इस सीजन में महाराष्ट्र कुल चीनी के एक-तिहाई हिस्से का उत्पादन करेगा। पिछले साल सूखा पड़ा था इसी वजह से उत्पादन बेहद कम था। किसानों के लिए दोनों ही साल खराब थे। पिछले साल चीनी की ज्यादा कीमतों की वजह से कोई बकाया नहीं था और मिल भुगतान करने के लिए तैयार थे। प्याज की कीमतों में सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव देखा जाता है और इसने कभी-कभी किसानों को काफी बेहतर प्रतिफल दिया जब इसकी कीमतें आसमान छू रही थीं। लेकिन वास्तविक लाभ किसानों को अभी नहीं मिला है क्योंकि जब भी उत्पादन बढ़ता है कीमतें कम हो जाती हैं। राज्य में नासिक के नजदीक लासलगांव मंडी प्याज का सबसे बड़ा बाजार है और एनएचआरडीएफ के मुताबिक प्याज की बिक्री 7.6 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से हो रही थी। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, महाराष्ट्र के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है इसीलिए उन्होंने किसानों को यह सलाह दी है कि वे प्याज का भंडार तैयार करें ताकि जब मई के बाद आपूर्ति सीजन खत्म होना शुरू हो तब उसकी बिक्री की जाए। महाराष्ट्र प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है जिसकी 25 फीसदी हिस्सेदारी है और इस साल राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने राज्य में 53 लाख टन प्याज के उत्पादन का अनुमान लगाया था। पिछले साल तक प्याज की कीमतें बेहद कम 5 रुपये से नीचे थीं जिसकी वजह से भी किसानों में रोष है।

पाइप से पेयजल आपूर्ति में महाराष्ट्र सबसे आगे

नई दिल्ली (विसं)। पाइपलाइन के जरिए पेयजल आपूर्ति कराने के मामले में महाराष्ट्र की स्थिति देश में सबसे अच्छी है। देश में फिलहाल तीन करोड़ तीन लाख से ज्यादा परिवारों को पेयजल का पाइपलाइन का कनेक्शन दिया गया है। इसमें अकेले महाराष्ट्र में ही 49 लाख से ज्यादा घरेलू कनेक्शन दिए गए हैं। केन्द्रीय पेयजलय एवं स्वच्छता राज्य मंत्री एसएस अहलूवालिया ने लोकसभा में यह जानकारी दी। सरकार वर्ष 2030 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पाइप लाइन के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके लिए मंत्रालय ने वर्ष 2017 से 2030 तक कार्यनीति तैयार किया है। मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत सात हजार करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। इस राशि को कार्यक्रम दिशा निर्देशों के पूर्व अनुमोदित मानदंडों के आधार पर राज्यों को आबंटित किया जाएगा।

मार्च के अंत तक आ सकता है कृषि फसल खरीद का मॉडल

नई दिल्ली (विसं)। किसानों को उनके उत्पाद का पर्याप्त मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार मार्च के अंत तक खरीद फॉर्मूले को अंतिम रूप दे सकती है। इसके लिए सरकार अपने मार्केट एश्योरेंस स्कीम (एमएएस) या मध्य प्रदेश सरकार के मूल्य अंतर वित्तपोषण कार्यक्रम (भावांतर योजना) या राज्यों के सुझाव के आधार पर निजी एजेंसियों की ओर से खरीद को लेकर आवश्यक बदलाव कर सकती है। राज्य सरकारों व नीति आयोग की बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मार्च के आखिर तक इस व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में घोषणा की थी कि नीति आयोग किसानों को उनके उत्पाद का पर्याप्त दाम दिलाने के लिए व्यवस्था बनाएगा। वित्त मंत्री ने यहभी घोषणा की थी कि नीतिगत निर्णय के रूप में सरकार ने किसानों के उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने का फैसला किया है। राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और कृषि, खाद्य, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्य रूप से 3 विकल्पों पर चर्चा की। इसमें केंद्र सरकार को एमएएस शामिल है। इसके मुताबिक राज्य सरकारें पूरी खरीद करेंगी जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, जबकि केंद्र सरकार एमएसपी के एक हिस्से की भरपाई करेगी।

उदित ओवरसीज प्रा.लि.

राजस्थान सरकार द्वारा उर्वरक अब मान्यता प्राप्त दरों व अनुदान पर उपलब्ध

फर्टिलाइजर
1. जिंक सल्फेट 21 प्रश.
2. जिंक सल्फेट 33 प्रश.
3. फेरस सल्फेट 19 प्रश.
4. कॉपर सल्फेट 24 प्रश.
5. मैग्नीशियम सल्फेट 9.6 प्रश.

बायो फर्टिलाइजर
1. राइजोबियम पाउडर
2. एजेटोबेक्टर पाउडर
3. पी.एस.बी. पाउडर

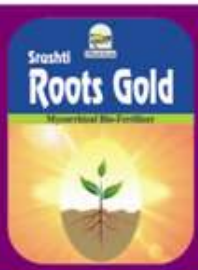

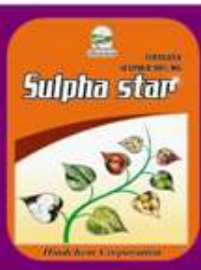

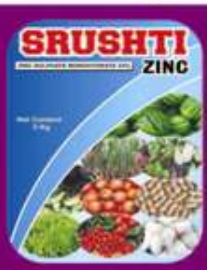

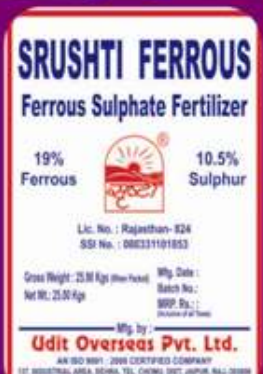

FERTILIZER
- SRUSHTI HIZINC (MICRONUTRIENT MIXTURE)
- ZINC EDTA 12%
- FERROUS EDTA 12%
- BORON 20%
- COPPER SULPHATE 24%
- SULPHUR 90% WG

BIO FERTILIZERS
- MYCORRHIZA (ROOTS GOLD)
- AZOSPIRILLUM
- PHOSPHATIC SOLUBILISING BACTERIA (PHOS UP)
- POTTASIUM MOBILIZING (POTA RISE)

WELCOME INQUIRY Contact : 7975653498 (Rajesh

137, Industrial Area Dehra, Tehsil Chomu, Dist, Jaipur

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - सुरेश जी. शर्मा की ओर से सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, शर्मा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-63 से मुद्रित किया और 307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड़ (प), मुंबई-400064 यहां से प्रकाशित किया। सम्पादक : सुरेश जी. शर्मा, Contace Detail : Tel. 022-66998360/61, Fax : 022-66450908
E-mail : info@srushtiagronews.com, website : www.srushtiagronews.com RNI No. MAHHIN/2013/49425